नवसर्जन संस्कृति

TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 228
दि. 19.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

गले मिले, हाथ हिलाया, भव्य विदाई के साथ ओमान से दिल्ली रवाना हुए पीएम मोदी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं. अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत पीएम मोदी बुधवार को ओमान पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. यहां मुक्त व्यापार समझौते पर भी भारत और ओमान ने हस्ताक्षर किए. गुरुवार को पीएम मोदी ओमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए. एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने सुल्तान हैथम बिन तारिक आए थे. पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. गुरुवार को उन्होंने ओमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को भव्य विदाई दी गई. ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया. सुल्तान से पीएम मोदी गले मिले, हाथ हिलाया और दोस्ती की एक नई शुरूआत कर ओमान से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए. पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा के दौरान अंतिम पड़ाव में ओमान पहुंचे थे. यहां उनका बुधवार को भव्य स्वागत किया गया.

मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसपर कहा- हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार मिल रहे सम्मान 140 करोड़ भारतीयों की ताकत और उनके नेतृत्व में एक बदलते राष्ट्र के रूप में भारत के उभरने का प्रमाण हैं. उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' दिया जाना, राजनेता के तौर पर उनकी पहचान और एक वैश्विक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता का बड़ा प्रमाण है. पीएम मोदी को यह पुरस्कार ओमान की उनकी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रदान किया गया. वह जॉर्डन और इथियोपिया के बाद अंतिम पड़ाव के तौर पर वहां

पहुंचे थे.

मुक्त व्यापार समझौते से द्विपक्षीय संबंधों में आएगी नई ऊर्जा- पीएम मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (उएढअ) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा और दोनों देशों में वृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की. उन्होंने अपने संबोधन में मांडवी से मस्कट तक दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया जो वर्तमान समय में जीवंत वाणिज्यिक आदान-प्रदान की आधारशिला हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंध सदियों से निर्मित विश्वास और मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं.

मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद और चमड़े के सामान सहित भारत के 98 फीसदी निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी. सीईपीए को भारत-ओमान के साझा भविष्य की रूपरेखा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों से इस समझौते की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का आ'ान किया है. पीएम मोदी ने कहा- आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी. व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा.

नए स्वरूप में दिखेगा भातखंडे विवि : योगी

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय अब जल्द ही अपने नए स्वरूप में नजर आएगा, इसके लिए लगभग छह एकड़ भूमि प्रदान की गई है, जहां वैश्विक मानकों के अनुरूप नया परिसर विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक ऑडिटोरियम, ओपन थिएटर, समृद्ध लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं होंगी। पुराने परिसर को संगीत और कला के संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के तीन दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। कलामंडपम प्रेक्षागृह

में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में होती है। जैसे किसी मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति को उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान ने सौ वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया है, बल्कि उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़कर प्रतिष्ठित भी किया है। उन्होंने कहा कि एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उप राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में शामिल हुए

उप राष्ट्रपति ने क्रिसमस को शांति और करुणा का उत्सव बताया

उप राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत की आध्यात्मिक भावना से मेल खाता है

उप राष्ट्रपति ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा में ईसाई समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की

उप राष्ट्रपति ने कहा, "भारत की एकता एकरूपता में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और साझा मूल्यों में निहित है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को बढ़ावा देते हैं"

(जीएनएस)।

उप राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लिया और त्योहार से पहले ईसाई समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीं।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस शांति, करुणा, विनम्रता और मानवता की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाए गए प्रेम, सद्भाव और नैतिक साहस का संदेश शाश्वत प्रासंगिकता रखता है और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो सह अस्तित्व, करुणा और मानवीय गरिमा के सम्मान पर जोर देती हैं।

भारत में ईसाई धर्म की लंबी उपस्थिति को याद करते हुए, उप राष्ट्रपति ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा में ईसाई समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुधार और मानव विकास में समुदाय के निरंतर कार्यों की सराहना की, जो देश के सुदूरतम क्षेत्रों तक भी पहुंचे हैं और इसे राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया।

प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करेंगे, प्रधानमंत्री आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क आयुष मार्क का भी शुभारंभ करेंगे,

प्रधानमंत्री वर्ष 2021-2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे,

प्रधानमंत्री दिल्ली में डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे, शिखर सम्मेलन का विषय "संतुलन की पुनर्स्थापनाः स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास" है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 दिसंबर, 2025 को शाम 4:30 बजे भारत मंडपम,

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस वर्ष राज्य सरकार के विभागों द्वारा बजट अंतर्गत किए गए खर्च की सर्वग्राही समीक्षा बैठक आयोजित की

मुख्यमंत्री का विभागों को और अधिक सुदृढ़ आयोजन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने का सुझाव

अर्बन डेवलपमेंट द्वारा गठित क्वॉलिटी सेल की तरह अन्य विभागों को भी क्वॉलिटी एश्योरेंस के लिए कदम उठाने के दिशा-निर्देश

गांधीनगर,18 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर इस वर्ष 2025-26 के बजट अंतर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा नवंबर 2025 तक किए गए खर्च की समीक्षा की।

श्री पटेल ने इस समीक्षा के दौरान विभागों द्वारा 30 नवंबर 2025 तक बजट अंतर्गत किए गए खर्च की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजटीय प्रावधान के समक्ष खर्च में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया।

इतना ही नहीं; उन्होंने सभी विभागों को उनका आयोजन अधिक सुदृढ़ करके निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो एवं आगामी वर्ष की पहली तिमाही में खर्च में अधिक सुधार हो; इसके लिए भी दिशा-निर्देश दिए।

इस बैठक में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, परिवहन तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री

प्रवीणभाई माळी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सहभागी हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बजट आवंटन के समक्ष राज्य सरकार के विभागों द्वारा हुए खर्च की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए शुरू किए गए उपक्रम में आयोजित पूर्व की बैठक में हुए सुझावों के संदर्भ में खर्च की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की सर्वग्राही समीक्षा भी की। उन्होंने विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिस्टमैटिक टेस्टिंग तथा क्वॉलिटी मॉनिटरिंग करने का सुझाव देते हुए दिशा-निर्देश दिए कि यदि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई भी विसंगति ध्यान में आए, तो उस पर कड़े कदम उठाए जाएँ।

उन्होंने जोड़ा कि शहरी विकास विभाग द्वारा जिस प्रकार क्वॉलिटी सेल बनाया गया है, उसी प्रकार अन्य विभाग भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने वाली सभी योजनाएँ समय पर लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा सहायता पेंशन वास्तव में पात्रता रखने वाले वास्तविक लाभार्थियों को समय पर सहायता-लाभ मिलें।

उन्होंने हिमायत की कि सम्बद्ध विभाग ऐसी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने पास उपलब्ध डेटा का उपयोग करे। उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के प्रावधानों के समक्ष समय पर खर्च करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए और उसके बाद के आनुषांगिक कार्य पूर्ण कर भारत सरकार की ओर से अधिकतम फंड प्राप्त करने का जरूरी फॉलोअप लिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों को वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुँचे; इस प्रकार कार्य करने और जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज पर हो, उसे तेजी से पूर्ण कर सच्चे अर्थ में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने इस समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वित्त विभाग सहित सभी विभाग गुणवत्तायुक्त तथा समय पर खर्च सुनिश्चित करने के सघन प्रयास करेंगे।

सरकार पूरे भारत में कैंसर देखभाल, अनुसंधान और किफायती उन्नत उपचारों को बढ़ा रही है: डॉ. जितेंद्र सिंह

संसद में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैंसर देखभाल को चुनिंदा उत्कृष्टता से सार्वभौमिक पहुंच में बदला जा रहा है

टाटा मेमोरियल सेंटर में लगभग 60% कैंसर रोगियों का इलाज मुफ्त या मामूली कीमत पर किया जाता है: डॉ. जितेंद्र सिंह

कैंसर के बढ़ते मामले वैश्विक प्रवृत्ति है; शुरूआती पहचान से कई कैंसर ठीक हो सकते हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

देश में कैंसर के बढ़ते बोझ पर संसद में कई प्रश्नों के उत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कैंसर की रोकथाम, निदान, उपचार, अनुसंधान और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वहनीयता को मजबूत करने के लिए सरकार की बहुआयामी, भविष्य के लिए तैयार रणनीति की जानकारी दी।

मंत्री ने अस्पताल में भर्ती, कैंसर के बढ़ते मामले, दवाओं की सामर्थ्य, टीके, वैश्विक सहयोग और उन्नत परमाणु उपचार तक पहुंच से संबंधित चिंताओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य एकीकरण द्वारा संचालित कैंसर देखभाल को चुनिंदा उत्कृष्टता से सार्वभौमिक पहुंच में बदल रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को अक्सर अस्पताल में भर्ती के दौरान भावनात्मक और लॉजिस्टिकल तनाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रही है, साथ ही तृतीयक अस्पतालों पर रेफरल दबाव को कम करने के लिए जिला स्तर पर कैंसर विज्ञान सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

मंत्री ने बताया कि 2014 से देश भर में 11 टाटा मेमोरियल सेंटर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही 300 से ज्यादा अस्पतालों को कवर करने वाला नेशनल कैंसर केयर ग्रिड भी बनाया गया है, जो मरीजों के घरों के पास स्टैंडर्ड और आसानी से मिलने वाली कैंसर सेवाएं सुनिश्चित करता है। नवी मुंबई में प्लेटिनम ब्लॉक सहित बड़े विस्तार कार्य भी चल रहे हैं।

कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंताओं को दूर करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी ग्लोबल घटना है। इसके लंबी उम्र, पर्यावरणीय कारक, जीवनशैली में बदलाव और गैर-संक्रामक बीमारियों की जल्दी शुरूआत जैसे कारण हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में महाराष्ट्र के 4जी कनेक्टिविटी डेटा प्रस्तुत किए

श्री सिंधिया के अनुसार महाराष्ट्र लगभग शत प्रतिशत 4जी कवरेज हासिल करने के बाद तेजी से 5जी कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र राज्य अब शत प्रतिशत 4G कवरेज की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि राज्य भर में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अब तक लगभग 1,64,000 4G और 40,000 5G बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादत्त एम. सिंधिया ने माताबाड़ी पर्यटन सर्किट विकास पर आहूत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

त्रिपुरा को वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की एक व्यापक योजना

पर्यटन सेवाओं में ऐतिहासिक ज्ञान का संस्थागतकरण: सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

(जीएनएस)।

संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरआदित्य एम. सिंधिया ने आज त्रिपुरा में माताबाड़ी पर्यटन सर्किट के विकास पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार, सचिव तथा केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में माताबाड़ी सर्किट को एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। इसमें क्षमता निर्माण पर मजबूत जोर दिया गया, ताकि स्थानीय लोगों को पर्यटन से उत्पन्न अवसरों से सार्थक रूप से जोड़ा जाए और प्रेरित किया जाए, विशेष रूप से सतत आजीविका के संदर्भ में।

श्री सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि त्रिपुरा के इतिहासकारों को भी पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें पर्यटक गाइडों और सहायकों को प्रशिक्षित करने में लगाया जाए, ताकि राज्य के इतिहास का प्रामाणिक ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस प्रक्रिया को संस्थागत बनाया जाना चाहिए, जिसमें पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों के साथ समन्वित किया जाए।

पश्चिम रेलवे पर ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2025 का आयोजन

मुंबई, रेलवे अपने नेटवर्क पर सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होती है। इसी क्रम में, पश्चिम रेलवे द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (जो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है) के अवसर पर 08 से 14 दिसंबर 2025 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना तथा पश्चिम रेलवे द्वारा इस दिशा में की गई पहलों को उजागर करना था।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सप्ताह भर चले इस आयोजन के दौरान पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों, पाँच कारखानों एवं मुख्यालय में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सेमिनार, पंपलेट का वितरण, रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणाएँ, एसएमएस अलर्ट, बैनर प्रदर्शन आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसी सहभागितापूर्ण गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना था।

ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2025 के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के साथ अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार तथा प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर श्री रजनीश कुमार गोयल दिखाई दे रहे हैं।

किया गया, जिसकी अध्यक्षता पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने की। इस सेमिनार में अपर महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सेमिनार में भारतीय रेल एवं पश्चिम रेलवे द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के समर्थन में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

श्री विनीत ने आगे बताया कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2024झ 2025 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंद्रह रेलवे अधिकारियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा नवोन्मेषी ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन हेतु मेरिट प्रमाणपत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अपने समापन संबोधन में महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण पहलों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे सतत एवं समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नवीन तकनीकों को अपनाने तथा कर्मचारियों एवं हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के विभाग के सक्रिय दृष्टिकोण की प्रशंसा की।

महाप्रबंधक ने भविष्य में ऊर्जा संरक्षण उपायों को और अधिक सुदृढ़ एवं सतत बनाने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझाव भी दिए। उन्होंने निरंतर निगरानी, नवीन ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग तथा सभी विभागों की सामूहिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

पश्चिम रेलवे संगठन के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पहलों को सुदृढ़ करने एवं निरंतरता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

'सीएम कान में कहकर वोट कटवा रहे', अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर एसआईआर घोटाले का आरोप

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज (18 दिसंबर 2025) लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अखिलेश ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए।

अखिलेश ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए सरकार जानबूझकर समाजवादियों के वोट कटवा रही है। उन्होंने इसे चुनावी साजिश करार दिया और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, कोडीन कफ सिरप घोटाले, प्रदूषण और अन्य मुद्दों पर भी योगी सरकार को घेरा। आइए, इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं- क्या है रक्क्र आरोपों की जड़ क्या है और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है?

विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें दोहराए गए नाम, मृतकों या गैर-मौजूद मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। उत्तर प्रदेश में रक्क्र की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि इससे करीब 4 करोड़ फर्जी वोट हटाए गए हैं। लेकिन विपक्षी दल, खासकर सपा और कांग्रेस, इसे एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) जैसी साजिश बता रहे हैं।

उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया अल्पसंख्यकों, गरीबों और विपक्षी समर्थकों को टारगेट कर रही है, जिससे चुनावी बैलेंस बिगड़ सकता है। अखिलेश यादव ने इसे 'ठफ्ठ का छद्म रूप' बताया, जहां स्पेलिंग मिस्टेक जैसी छोटी गलतियों से नाम काटे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग चुप है।

'मुख्यमंत्री कान में कहकर वोट कटवा रहे हैं'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों को बचा रही है, जबकि विपक्ष

के वोटरों पर दबाव बनाया जा रहा है। यहां उनके प्रमुख बयानों का सारः-

वोट कटवाने का दावाः 'मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं, वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। कान में कहकर आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए।' अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर SIR रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोट कट गए? 'अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं, यह मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठकर उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है, उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है?'

राजनीतिक साजिश का आरोपः अखिलेश ने आरोप लगाया कि रक्क्र के जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ है। उन्होंने कहा कि जो ऐप रक्क्र के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वह उसी कंपनी का है जिसने चुनावी बॉन्ड्स से बीजेपी को फंड दिया था। इससे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर 4 करोड़ वोट कटे, तो प्रति विधानसभा सीट (कुल 403) औसतन 84 हजार वोट हटाए गए, जो बिना प्रशासनिक दबाव के संभव नहीं।

यह आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और वोटर लिस्ट में बदलाव सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष का मानना है कि इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, खासकर मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोट प्रभावित होंगे।

अखिलेश ने कोडीन कफ सिरप के घोटाले पर भी सरकार को घेरा। यह मुद्दा हाल ही में सुर्खियों में आया, जहां अवैध रूप से कोडीन युक्त सिरप की बिक्री और मिलावट की शिकायतें हैं। अखिलेश ने कहाः- 'कोडीन को लेकर आम लोग और गरीब लोग चिंतित हैं, प्रधान संसद के यहां से शुरू होकर कोडीन कफ सीरप को भेजा जा रहा है। माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया...कोडीन भैया तो सबने देखा।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही है, और यह एक बड़ा घोटाला है। बैकग्राउंड में, कोडीन एक प्रतिबंधित दवा है, जिसका दुरुपयोग नशे के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में हाल के छापों में बड़े पैमाने पर मिलावटी सिरप बरामद हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही।

प्रदूषण और पर्यावरण पर सवालः 'समाजवादियों का स्टेडियम, मैच नहीं हो पाया'

अखिलेश यादव (अ॔ ीरॅ ि५) ने लखनऊ के प्रदूषण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहाः- 'इस समय पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया और यह वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो और एक्यूआई का डाटा सरकार के पास अपना है। इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है।' लखनऊ का अदक हाल में 300 से ऊपर रहा है, जिससे मैच रद्द हुए। अखिलेश ने इसे सरकार की विफलता बताया, जबकि सपा शासन में बने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर अपनी उपलब्धियां गिनाईं।

राजनीतिक असर और रिएक्शन

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्क्र विवाद को और गमार्ती है, जो पहले से ही योगी और अखिलेश के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जबकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। सोशल मीडिया पर SIR2025 और Akhilesh ट्रेंड कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि रक्क्र रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अगर आरोप साबित हुए, तो यह चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। फिलहाल, योगी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

यह विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है - क्या रक्क्र निष्पक्ष अपडेट है या चुनावी हथियार? फैंस और विश्लेषक आगे की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं।

लोकसभा में वीबी जी राम जी विधेयक पर हाई वॉल्टेज ड्रामा

(जीएनएस)।

संसद का शीतकालीन सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा बिलों को पास कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल भी हमलावर हैं। गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल के पर्चे फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फेंक दिए। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

राज्यसभा में भी परमाणु उर्जा संशोधन बिल पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के बिल को लेकर जो भी शंकाएं हैं और आपत्ति हैं, सरकार उन पर विचार करने के लिए तैयार है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

– लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर VB-G Ram G बिल किए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने बिल के विरोध में कहा कि इस सरकार को बापू के नाम से भी परहेज है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध करना जानता है और यह नकारात्मक राजनीति है।

– इस दौरान लोकसभा में भारी हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर ही बिल के पर्चे फाड़ दिए और उसे उछालकर कृषि मंत्री के ऊपर फेंक दिया। बिल के कुछ पर्चे स्पीकर ओम बिड़ला की तरफ भी गए थे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

– भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि सरकार इस बिल को SHANTI नाम दे रही है, लेकिन यह नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दिल्ली में प्रदूषण का मामला गमार्या

दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी ने दिल्ली का हाल बुरा कर दिया है। आज यह स्थिति है कि बच्चे-बूढ़े सांस नहीं ले पा रहे हैं। बीमारी की वजह से दिल्ली छोड़कर जाना पड़ रहा है। बीजेपी सांसदों ने सत्र के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की।

भाजपा के इस नेता ने चार साल बाद कटवाए बाल, जानें क्या ली थी प्रतिज्ञा, जो अब हो गई पूरी

(जीएनएस)।

भाजपा नेता राम कदम एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि चार साल बाद उन्होंने अपने बाल कटवाए हैं। राम कदम ने चार साल पहले बाल ना कटवाने की अनोखी प्रतिज्ञा अपने लिए नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र घाटकोपर के नागरिकों के लिए ली थी। अब चार साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर उन्होंने अपने बाल करटवाए हैं। राम कदम का वीडियो सामने आया है जिसमें वो लंबे-लंबे बाल कटवाते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं।

दरअसल, मुंबई के घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता था। चार साल पहले भाजपा नेता राम कदम ने तब ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो तक वो बाल नहीं कटवाएंगे जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र घाटकोपर के पहाड़ी इलाकों को पानी नहीं मिल जाता। वहीं राम कदम के आंदोलन और लंबे संघर्ष के बाद अब घाटकोपर के पहाड़ी क्षेत्र में पानी की समस्या हल होने पर उन्होंने अपने बाल कटवा दिए हैं।

4 नवंबर, 2022 को एक ट्वीट में, कदम ने अधिकारियों संग बैठक

की तस्वीर साझा कर थी और बाल ना कटवाने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को भी टैग भी किया था। घाटकोपर के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी एक पुरानी समस्या है। विधायक ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पानी प्रश्न सुलझाने के लिए महापालिका अधिकारियों से लगातार बैठकें की और जमकर सर्खियां बटोरी थी।

कदम की इस प्रतिज्ञा को तब खूब समर्थन भी मिला था। संदीप गिरकर ने प्रतिक्रिया दीः "'पानी' ही घाटकोपर और पार्कसाइट की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु आपकी भीष्म प्रतिज्ञा का हम पूरा समर्थन करते हैं।" अब देखना होगा कि क्या घाटकोपर की पानी समस्या हल होगी और क्या विधायक कदम अपनी शपथ पूरी कर पाएंगे।

कौन हैं राम कदम?

राम कदम महाराष्ट्र के प्रमुख राजनेताओं में से एक माने जाते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र विधान सभा के विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1972 को हुआ था।

रामकदम मुंबई के घाटकोपर वेस्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं।

अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से की थी और वर्ष 2009 में पहली बार विधायक बने।

बाद में राम कदम ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की।

रामकदम राजनीति और सार्वजनिक टिप्पणियाँ अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय रहती हैं, जिनमें कभी-कभी विवादित बयान भी शामिल रहे हैं।

'मुसलमान हिंदू की तरह करें पूजा', कौन हैं संघ नेता दत्तात्रेय होसबले? जिनके बयान पर मचा बवाल

(जीएनएस)।

"हिंदू धर्म सर्वोच्च है और अगर भारत में रहने वाले मुसलमान सूर्य नमस्कार करें, नदियों की पूजा करें, तो इससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह पूजा करनी चाहिए" ये बयान फरर के वरिष्ठ नेता-महासचिव दत्तात्रेय होसबले नेउत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दिया है। जिसपर चौतरफा विवाद हो रहा है।

दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ा अभ्यास है। इसमें कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है। उनके मुताबिक, अगर मुसलमान भी सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करते हैं तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मस्जिद जाने या नमाज छोड़ने से रोका जाएगा। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म सबके लिए बोलता है और प्रकृति, जीव-जंतुओं और पर्यावरण के प्रति अहिंसा की शिक्षा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं दत्तात्रेय होसबले?

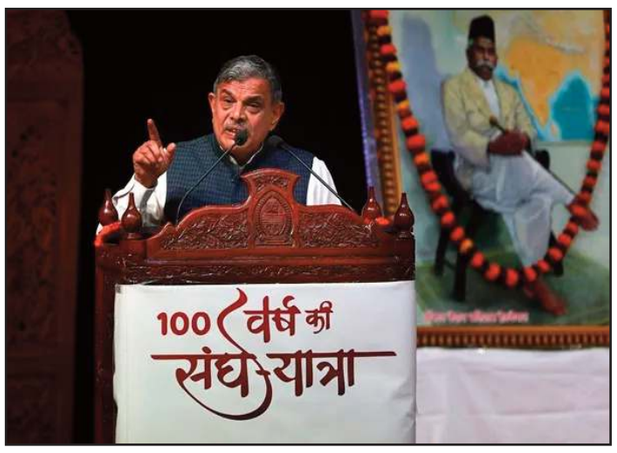

: कौन हैं दत्तात्रेय होसबले?

दत्तात्रेय होसबले फरर के मौजूदा सरकार्यवाह यानी महासचिव हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1954 को कर्नाटक के शिमोगा में हुआ। उनका परिवार शुरू से फरर से जुड़ा रहा है।

उन्होंने 1968 में फरर जॉइन किया और 1972 में अइश्ढ से जुड़े। आपातकाल के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया, जिसके चलते उन्हें एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा।

शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन और मैसूर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

1992 में होसबले अइश्ढ के संगठन मंत्री बने। 2009 में उन्हें फरर का सह-सरकार्यवाह बनाया गया।

20 मार्च 2021 को वे फरर के सरकार्यवाह बने। 2024 में वे इस पद पर दोबारा चुने गए।

माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके करीबी संबंध भी उनकी भूमिका को मजबूत बनाते हैं।

'हिंदू धर्म सर्वोच्च है' वाली लाइन पर आपत्ति

दत्तात्रेय होसबले के बयान का सबसे विवादित हिस्सा रहा "हिंदू धर्म सर्वोच्च है"। कई लोगों ने इसे एक धर्म को दूसरे से ऊपर बताने की कोशिश माना। वहीं, "मस्जिद जाने से नहीं रोका जाएगा" जैसी टिप्पणी को भी आलोचकों ने 'समावेशन के नाम पर आत्मसात करने' का संकेत बताया।

आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान धर्म को संस्कृति, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जोड़कर सामान्य सार्वजनिक व्यवहार के रूप में पेश करते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनता है।

इस कार्यक्रम में होसबले ने 'मानव धर्म' को सबसे ऊपर रखने की बात कही। साथ ही देश के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, यह सभी जानते हैं। इस टिप्पणी ने भी सियासी माहौल को और गरमा दिया।

यह पहली बार नहीं है जब दत्तात्रेय होसबले विवादों में आए हों। जून महीने में उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों पर बहस की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। इस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संविधान और बराबरी के मूल्यों पर हमला बताया था।

दत्तात्रेय होसबले का बयान ऐसे वक्त में आया है, जब देश में धर्म, संस्कृति और संविधान को लेकर बहस पहले से ही तेज है।

माल्टा महोत्सव में पहुंचे डीएम, पहाड़ी नमक पिसा और खटाई का भी लिया स्वाद, वायरल हो रहा ये अंदाज

(जीएनएस)।

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। युवा जिलाधिकारी प्रतीक जैन सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। हाल ही में रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन माल्टा महोत्सव में पहुंचे।

उन्होंने माल्टा महोत्सव में स्टॉल लगा रही महिलाओं से बात की। उन्होंने महिलाओं से माल्टा, नमक के बारे में जानकारी ली। साथ ही डीएम ने नमक को बनाने के बारे में भी पूछा। जिसके बाद महिलाओं ने उन्हें पहाड़ी नमक लूंण के बारे में बताया।

महिलाओं ने बताया कि इसे सिलौटा में पिसा जाता है, बस डीएम ने सिलौटा पर नमक भी पीसा। डीएम का पहाड़ी नमक पिसते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पहाड़ों में माल्टा का खूब उत्पादन हो रहा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रुद्रप्रयाग में माल्टा महोत्सव आयोजित हो रहा है।

महोत्सव के दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्वयं सहायता समूहों की

महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे माल्टा से बने उत्पादों की जानकारी ली और उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रस्तुति की सराहना की। जिलाधिकारी ने स्वयं माल्टा से बने विभिन्न उत्पादों और खटाई का स्वाद भी लिया।

डीएम का ये अंदाज सबको खासा पसंद आ रहा है। वे सीधे लोगों के बीच पहुंचकर सरल तरीके से बात करते हैं। जिससे लोगों को एक पल के लिए ये भी एहसास नहीं होता है कि वे एक डीएम के साथ हैं। ऐसे में डीएम प्रतीक धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।प्रतीक जैन रुद्रप्रयाग के सबसे युवा 32 साल के जिलाधिकारी हैं। जबसे डीएम का चार्ज लिया है तब से लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतीक जैन पैदल ही केदारनाथ धाम पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की समस्याओं को मौके पर ही सुना और उनका निस्तारण करने की कोशिश की।

आपदा के दौरान डीएम प्रभावितों से मिलने नदी पार करके कई किमी पैदल चलकर पहुंचे। अभी हाल ही में उखीमठ मंदिर में शिव साधना करते और भजन गाते हुए वायरल हुए। प्रतीक जैन मूलरुप से राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं। जो कि 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, खंड शिक्षा अधिकारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते दबोचा, मचा हड़कंप

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी ने पुलिस मॉडर्न स्कूल, 40 बटालियन पीएसी, हरिद्वार की मान्यता का औपबंधिक प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

हरिद्वार जिले में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने 40 वाहिनी पीएसी के पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता से जुड़े मामले में बीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मंगोलपुर स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस की टीम ने उसे भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों आरोपियों को लेकर देहरादून रवाना हो गई। जिसके बाद से पूछताछ जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल की मान्यता के लिए नवीनीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता ने जब खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर से नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने को कहा तो उन्होंने रिश्वत की एवज में बीस हजार रुपए मांगे। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रोशनाबाद स्थित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर छापेमारी की।

विजिलेंस की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौड़ को रोशनाबाद जिला मुख्यालय में ही दबोच लिया। बृजपाल सिंह राठौर बहादराबाद में तैनात हैं। शिकायत पर टीम ने आज अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम ने अभियुक्त के संबंध में अन्य जानकारी जुटा रही है। साथ ही अभियुक्त के अन्य दस्तावेज और जरुरी जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही विजिलेंस अभियुक्त की संपत्तियों को लेकर भी अहम जानकारी जुटा रही है।विजिलेंस की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में बढ़ता भारत विरोध का जुनून

भारत और बांग्लादेश के संबंध जबरदस्त वूटनीतिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। बुधवार देर शाम को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाकर दो टूक बता दिया गया है कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा आपकी यानि बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। उनसे यह भी बता दिया गया है कि भारत बांग्लादेश के हर उकसावे को नजरंदाज भले ही कर रहा है किन्तु उसे गंभीरता से लेता है। दरअसल 15 दिसम्बर को बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पाटा यानि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए भारत को धमकी दी कि "मैं भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आप उन ताकतों को शरण देते हैं जो बांग्लादेश की संप्राभुता, क्षमता, मताधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते, तो बांग्लादेश भारत के सभी सात पूवरेत्तर राज्यों को अलग करने के लिए अलगाववादियों को शरण देगा।" यह अब्दुल्ला प्राधानमंत्री पद से शेख हसीना को हटाने वालों में प्रामुख हैं। वह हसीना को भारत द्वारा दिए गए आश्रय पर नाराजगी व्यक्त कर रहा था। असल में गत वर्ष जबसे बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करके देश में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा समर्थित तत्वों की सरकार बनी है, उसने भारत के खिलाफ खुराफात शुरू कर दी है। शेख हसीना जब तक सत्ता में थी, तब तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों खासकर जमायत-ए-इस्लाम को नियंत्रित कर रखा था। किन्तु अंतर्राष्ट्रीय साजिश करके जैसे ही शेख हसीना को सत्ता से हटाया, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भारत के सात पूवरेत्तर राज्यों अरुणाचल प्रादेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शेष भारत से अलग करने की खुलेआम धमकी देना शुरू कर दी है। सच तो यही है कि भारत विरोधी ताकतों के मस्तिष्क में यह बात पहले से भ्रम ग्रांथि के रूप में विद्यमान है कि यदि भारत को ब्लैकमेल करना हो अथवा उसे सौदेबाजी के लिए तैयार करना है तो सेवन सिस्टर्स को अलग करने का डर दिखाना जरूरी होगा। हसनत की सनक देखिए, वह भारत को झुकाने के लिए पूवरेत्तर के सभी सातों राज्यों को अलग करने की धमकी भारत को दे रहा है! उसका कोई भी उचित तर्व नहीं है जिससे कि पता चले कि भारत के प्राति उसकी ईर्ष्या और शत्रुता का कारण वैध है! मात्र भारत को अपनी प्रासंगिकता का बोध कराने की छटपटाहट में कभी-कभी विघ्न संतोषी बांग्लादेश से ऐसी खुराफाती आवाज उठा ही देते हैं। इस तरह के सनकी नेताओं की षडांत्रकारी धमकी से भारत डरता भी नहीं हैं क्योंकि बांग्लादेश की घिग्घी तो कभी भी बंद की जा सकती है, डर मात्र इस बात का बना रहता है कि उन्मादी भीड़ ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को क्षति न पहुंचा दे! बांग्लादेश शेख हसीना के शासनकाल में सेक्युलर होने का दावा कर रहा था क्योंकि मजहबी उन्मादी और हिसक उग्रावादी संगठन या तो देश में रहकर गुमनाम हो गए थे अथवा उन्होंने नए संगठन बनाकर खुद को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का दिखावा कर लिया था। उन्होंने कभी भी बांग्लादेश को सेक्युलर स्टेट स्वीकार किया ही नहीं था। अब उन्हें अवसर मिला है क्योंकि हिफाजते इस्लाम, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी (बीजेआई), इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (आईंएबी), इस्लामी ओइक्या जोते (आईंओजे), बांग्लादेश तरीकत पेडरेशन (बीटीएफ) जैसी घोर सांप्रादायिक पार्टियां बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए आतुर हैं। इन्हें पाकिस्तान की जमायत-ए-इस्लामी के माध्यम से आईंएसआईं की तरफ से वित्तीय सहायता तो मिलती ही है साथ ही बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह मजहबी कट्टरपंथी राष्ट्र बनाने की प्रोरणा भी मिलती है। पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों को अनुकरणीय लग रहा है। यही कारण है कि वे तो यह चाहते हैं कि भारत उससे संपर्व बिल्वुल सीमित कर ले। यही कारण है कि आए दिन ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले होते रहते हैं। भारत ने इन दिनों बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया है। जब आए दिन

AB PMJAY-MA अंतर्गत लाभार्थियों को दावों का भुगतान करने में गुजरात प्रथम स्थान पर

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - मुख्यमंत्री अमृतम (AB PMJAY-MA) अंतर्गत गुजरात में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को समाविष्ट किया गया

ऑल इंडिया सर्विसेज (एआईएस) तथा राज्य सरकार के अधिकारियों, पेंशनभोगियों को अइ ढटखअ-टअ योजना का लाभ लेने के लिए 'कर्मयोगी स्वस्थ सुरक्षा योजना', जी कैटेगरी अंतर्गत लगभग 6.40 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण

गांधीनगर, 18 दिसंबर : गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरातियों के स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से 'स्वस्थ गुजरात, समृद्ध गुजरात' का मंत्र दिया था। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुदूरवर्ती मानव तक पहुँचे और कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री अमृतम योजना के साथ जोड़ा गया है।

संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना झ मुख्यमंत्री अमृतम (AB PMJAY-MA) अंतर्गत राज्य के 1,20,14,556 परिवारों को समाविष्ट किया गया है।

इसके अलावा; जुलाई-2023 में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में AB PMJAY-MA अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार वार्षिक बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है।

यह बात दशार्ती है कि गुजरात ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक मजबूत तथा सुलभ बनाया है, जो राज्य में सुशासन का उत्तम उदाहरण है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल कहते हैं, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड देकर गरीब एवं मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज समाज को निरामय रखने के लिए हमने गुजरात में योग से आयुष्मान तक की परियोजनाएँ लागू की हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत हमने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 10 लाख रुपए की है। इस योजना से गरीब एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोगों को गंभीर बीमारियों में निःशुल्क उपचार मिल रहा है। आज सरकारी अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं। स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ गुजरात के

माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हम साकार करेंगे।'

AB PMJAY-MA अंतर्गत आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए होने से प्रीमियम राशि में वृद्धि

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - मुख्यमंत्री अमृतम (AB PMJAY-MA) अंतर्गत जब 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, तब 1 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2022 तक प्रति परिवार प्रीमियम राशि 2177.10 रुपए थी और उस समयावधि के दौरान कुल वित्तीय खर्च 1681.20 करोड़ रुपए हुआ था। इसके बाद 11 जुलाई, 2022 से 10 जुलाई, 2023 के दौरान प्रीमियम राशि 1492 रुपए थी, जिस दौरान कुल वित्तीय खर्च 1363.52 करोड़ रुपए हुआ था।

10 जुलाई 2023 को राज्य सरकार द्वारा योजनांतर्गत देय आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई, जिससे प्रीमियम राशि बढ़कर प्रति परिवार 3708 रुपए हुई है। कुल वित्तीय खर्च की बात करें, तो 11 जुलाई 2023 से 10 जुलाई 2024 के दौरान कुल वित्तीय खर्च 2676.26 करोड़ रुपए, जबकि 11 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2025 के दौरान कुल वित्तीय खर्च 3210.03 करोड़ रुपए हुआ है।

AB PMJAY-MA योजना अंतर्गत राज्य में कुल 2090 अस्पताल एम्पैनल्ड हैं, जिनमें 1132 सरकारी तथा 958 निजी अस्पताल हैं। इस योजनांतर्गत नवंबर 2025 तक कुल 2299 प्रोसीजरों तथा 50 एसआरएस प्रोसीजरों को समाविष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों के दावों का भुगतान करने में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है।

राज्य सरकार के सभी कर्मयोगियों तथा पेंशनभोगियों के लिए 'कर्मयोगी स्वस्थ सुरक्षा योजना'

गुजरात सरकार द्वारा मई 2025 में राज्य के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए गुजरात कर्मयोगी स्वस्थ सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के फिक्स पे कर्मचारियों के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज (एआईएस) के अधिकारियों व पेंशनभोगियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिजनों को भी अइ ढटखअ-टअ अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार का लाभ दिया जाता है। गुजरात कर्मयोगी स्वस्थ योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मयोगियों तथा पेंशनभोगियों को जी सीरिज का अइ-ढटखअ-टअ कार्ड दिया जाता है। जी कैटेगरी अंतर्गत कुल लगभग 6.40 लाख लाभार्थी हैं।

66 वर्षीय फारुकभाई को हृदय रोग के उपचार के लिए अइ ढटखअ-टअ अंतर्गत मिली 5,24,040 रुपए की आर्थिक सहायता

अहमदाबाद निवासी 66 वर्षीय फारुकभाई खिमाणी एक जनरल स्टोर चलाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। फारुकभाई को हृदय में दर्द होने के बाद यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर लाया गया। उनकी ईसीजी रिपोर्ट कराई गई, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिसीज का निदान हुआ। उन्हें हृदय की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, जिसके लिए बहुत खर्च होने की संभावना थी। इस समय उनकी सहायता में आई प्रधानमंत्री जन आरोग्य झ मा अमृतम योजना (ढटखअ-टअ), जिसके तहत उन्हें राज्य सरकार द्वारा 5,24,040 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मई 2025 में ढटखअ-टअ योजना अंतर्गत सहायता से फारुकभाई की कोरोनरी एंजियोग्राफी तथा उसके बाद कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग (सीएबीजी) की सर्जरी की गई। इसके बाद हाल ही में यानी दिसंबर 2025 में ही उन्हें साँस लेने में दिक्कत होने पर यूएन मेहता अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया और वहाँ उनकी सीआरटी-पी इम्प्लांट की सफल सर्जरी की गई है। हाल में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और वे राहत का अनुभव कर रहे हैं। फारुकभाई कहते हैं, 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मेरे और मुझ जैसे मरीजों के लिए बहुत सहायक हो रही है। राज्य के गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाओं के लिए सरकार ने यह योजना लागू की, जिसके लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद !'

जी राम जी क्या है? कितना मिलेगा पैसा? क्या मनरेगा खत्म हो गया?

मनरेगा का नाम बदल गया है, लेकिन सवाल लोगों के मन में कई हैं। सरकार ने जिस नए कानून को मंजूरी दी है, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) जिसे संक्षेप में VB G RAM G Bill कहा जा रहा है।

संसद में इसे लेकर बहस भी हुई और 'वी बी जी राम जी बिल' 18 दिसंबर को लोकसभा में पास कर दिया गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि जी राम जी आखिर है क्या, इसमें मजदूरी कितनी मिलेगी और मनरेगा से यह कितना अलग है। आइए जानें जी राम जी से जुड़े हर सवाल का जवाब।

VB G RAM G Bill 2025 को सरकार ग्रामीण रोजगार नीति का नया अध्याय बता रही है। मनरेगा की जगह अब एक ऐसी योजना लाई गई है, जो रोजगार के साथ-साथ गांवों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका पर फोकस करती है। इस बिल के कानून बनते ही मनरेगा पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

▶ VB G RAM G Bill का फुल फॉर्म क्या है?

VB G RAM G का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है -विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। अंग्रेजी में इसे Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाली नई सरकारी योजना है।

मनरेगा की जगह 'जी राम जी' बिल लोकसभा में पास, रोजगार में आएंगे ये 10 बदलाव

मनरेगा की जगह 'जी राम जी' बिल लोकसभा में पास, रोजगार में आएंगे ये 10 बदलाव

▶ जी राम जी क्या है?

वीबी जी राम जी असल में मनरेगा का नया रूप है। सरकार ने मनरेगा की जगह नए नाम, नए ढांचे और नए नियमों के साथ पेश किया है। यह योजना सीधे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है, जिसमें गांवों को सिर्फ मजदूरी देने की जगह लंबे समय के विकास से जोड़ा गया है।

बिल में दर्ज उद्देश्य के मुताबिक बीते करीब दो दशकों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को काम देकर उनकी आय को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ गांवों की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदली है, ऐसे में इस व्यवस्था को नए सिरे से ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई।

नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी ग्रामीण परिवार बिना कौशल वाला श्रम करने को इच्छुक होगा, उसे हर साल 125 दिन तक वेतन वाला रोजगार दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि मनरेगा का नाम पहले सिर्फ नरेगा था। 2009 के चुनाव से पहले इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। सरकार का कहना है कि अब रोजगार योजना को एक नए विजन के साथ लाया गया है, जिसमें विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव और रोजगार युक्त गांव की सोच है। इसी वजह से नया नाम और नया कानून लाया गया है।

मनरेगा गया, 'जी राम जी' आया! नाम के साथ क्या-क्या बदला? रोजगार के नियम, खर्च से जुड़े 5 सवाल-जवाब

कितने दिन का रोजगार मिलेगा?

सबसे बड़ा बदलाव यही है। मनरेगा में जहां 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, वहीं अब 125 दिन की गारंटी दी गई है। हालांकि खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए बोआई और कटाई के समय करीब 60 दिन काम नहीं मिलेगा। बाकी बचे दिनों में पूरे 125 दिन का रोजगार देने का दावा किया गया है।

▶ जी राम जी में मजदूरी कितनी मिलेगी?

इस बिल में मजदूरी के लिए कितना पैसा मिलेगा, इसकी फाइनल दर तय नहीं की गई है। कानून में कहा गया है कि मजदूरी की दरें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि नई योजना में मजदूरी मनरेगा से ज्यादा हो सकती है।

मनरेगा के तहत अभी मजदूरी राज्यों के हिसाब से ₹200 से ₹400 प्रतिदिन के बीच रहती है और पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। जैसे हरियाणा में ₹357 और मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में ₹221 दिए जाते थे। हालांकि ये अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है।

सबसे बड़ा अंतर क्या है?

कई अहम फर्क हैं।

पहला, मनरेगा का नाम बदलकर अब VB G RAM G कर दिया गया है।

दूसरा, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

तीसरा, मनरेगा में मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र देता था, लेकिन अब राज्यों को भी खर्च उठाना होगा। कुछ राज्यों में 10 प्रतिशत और कुछ में 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी होगी।

चौथा, खेती को प्राथमिकता देने के लिए काम के दिनों में ब्रेक तय किया गया है।

इस वी बी जी राम जी योजना में पैसा कहां से आएगा?

VB G RAM G अब केंद्र प्रायोजित योजना है। ज्यादातर राज्यों में खर्च का बंटवारा 60:40 होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया है। कुल अनुमानित खर्च करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये सालाना बताया गया है।

वी बी जी राम जी के योजना के तहत कौन से काम होंगे?

सरकार ने चार प्राथमिक क्षेत्र तय किए हैं।

पहला, पानी से जुड़े काम जैसे जल संरक्षण और सिंचाई।

दूसरा, गांवों की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क और कनेक्टिविटी।

तीसरा, आजीविका से जुड़े काम जैसे भंडारण और बाजार।

चौथा, मौसम आपदाओं से निपटने वाले काम।

▶ द9. जी राम जी में मजदूरी समय पर न मिली तो क्या होगा?

अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी और नियम अलग से बनाए जाएंगे।

▶ द10. क्या जी राम जी योजना किसानों के लिए भी फायदेमंद है?

सरकार का दावा है कि इससे किसानों को खेती के मौसम में मजदूरों की कमी नहीं होगी। काम रोकने की व्यवस्था से खेती प्रभावित नहीं होगी और गांव में स्थायी संपत्तियां बनेंगी।

▶ क्या मनरेगा पूरी तरह बंद हो जाएगी?

हां, मनरेगा को अब पूरी खत्म कर दिया जाएगा। मनरेगा की जगह ही नया बिल लाया गया है। बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि साल 2005 का MGNREGA कानून रद्द किया जाएगा। मतलब यह कि जैसे ही नया कानून लागू होगा, उसके बाद ग्रामीण रोजगार के लिए केवल VB G RAM G ही प्रभावी रहेगा।

VB G RAM G नया कानून कब लागू होगा और पुराने जॉब कार्ड का क्या बनेगा?

संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया कानून प्रभाव में आएगा। बिल में यह भी साफ किया गया है कि कानून लागू होने के बाद राज्यों को छह महीने के भीतर नई व्यवस्था तैयार करनी होगी। इस दौरान राज्यों को पुराने सिस्टम की जगह नया पंजीकरण और पहचान तंत्र लागू करना होगा।

एशिया कप से लेकर आईपीएल भगदड़ तक, 3 विवाद जिन्होंने हिला दिया भारतीय क्रिकेट

(जीएनएस)।

साल 2025 में भारतीय टीम ने नई उंचाइयों को छूने का काम किया। टीम इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी से लेकर एशिया कप तक बड़े इवेंट्स अपने नाम किये। फैन्स के यह एक तरह से यह यादगार साल बन गया लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली, जिससे निराशा हाथ लगी।

साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार जीतों के साथ-साथ तीन बड़े विवादों की वजह से भी चर्चा में रहा। इन घटनाओं ने न सिर्फ सुर्खियाँ बटोरीं, बल्कि क्रिकेट प्रशासन, आयोजन व्यवस्था और खेल भावना पर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

भारत-पाकिस्तान हैंडशेक मामला

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हाथ मिलाने की प्रक्रिया नहीं हुई। इस

घटना ने तुरंत तूल पकड़ लिया और सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट बोर्ड्स तक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा, जबकि कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि क्या क्रिकेट को मैदान के बाहर की राजनीति से अलग रखा जा सकता है?

मोहसिन नकवी एशिया कप फाइनल की ट्रॉफी लेकर भागे

एशिया कप में खिताबी मुकाबले के बाद पुरस्कार वितरण के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली, जब मंच पर मोहसिन नकवी अड़कर खड़े हो गए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने मना कर दिया और नकवी ने अपनी जगह खड़े होकर ट्रॉफी देने की जिद्द की। काफी समय तक ड्रामा होने के बाद नकवी ट्रॉफी को अपने साथ लेकर चले गए और यह अभी तक एशियं क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्थिति ऑफिस में रखी हुई है।

आरसीबी की जीत की खुशी मातम में बदली

आईपीएल में आरसीबी ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। इस फ्रेंचाइजी की ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजित सेलिब्रेशन इवेंट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इस घटना ने क्रिकेट आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। आरसीबी की जीत की खुशी तुरंत मातम में बदल गई।

ईशान किशन ने धोनी को छोड़ा पीछे, फाइनल में छक्के से शतक जड़ जीत ली ट्रॉफी, अनुकूल रॉय का भी रहा जलवा

(जीएनएस)।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा के खिलाफ बल्लेबाजी में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस बड़े मैच में झारखंड के बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और हरियाणा के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हरियाणा को हार मिली और ईशान किशन झारखंड के लिए टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं।

झारखंड की पारी की सबसे बड़ी कहानी कप्तान और विकेटकीपर ईशान किशन रहे। ईशान ने महज 49 गेंदों में 101 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए ईशान ने फाइनल को पूरी तरह झारखंड के पक्ष में मोड़ दिया।

ईशान किशन का साथ दिया कुशाग्र ने, जिन्होंने 38 गेंदों पर 81 रन की तेजतर्रार पारी खेली। कुशाग्र के

बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले। इसके अलावा अनुकूल रॉय ने नाबाद 40 रन और रॉबिन मिंज ने नाबाद 31 रन बनाकर अंतिम ओवरों में रन गति को और तेज कर दिया।

हरियाणा की गेंदबाजी की बात करें तो कोई भी गेंदबाज झारखंड के बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा सका। अंशुल कंबोज और सुमित कुमार को एक-एक विकेट मिला, लेकिन रन रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। समंत जाखड़ और अमित राणा जैसे गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए।

झारखंड के इस स्कोर के बाद हरियाणा को जीत के लिए 263 रन का लक्ष्य मिला। 263 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम फाइनल मुकाबले के दबाव में पूरी तरह बिखर गई। शुरूआती विकेट जल्दी गिरने से हरियाणा कभी भी मैच में वापसी नहीं कर सकी। विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल ने 22 गेंदों में 53 रन की तेज पारी खेलकर थोड़ी उम्मीद जगाई, जबकि समंत जाखड़ ने 17 गेंदों पर 38 रन बनाए। इसके अलावा निशांत सिंधु ने 31 रन जोड़े, लेकिन बढ़ता रनरेट हरियाणा पर भारी पड़ गया। पूरी टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई और झारखंड ने फाइनल मुकाबला 69 रन से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

ईशान किशन झारखंड के लिए यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। धोनी भी ऐसा नहीं कर पाए थे। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अनुकूल रॉय को ऑल राउंड प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

'मैं ऑस्कर ले आऊंगा', 'धुरंधर' की सफलता के बाद इस स्टार का बड़ा दावा! नाम जान हो जाएंगे हैरान

(जीएनएस)।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और एक्शन के साथ-साथ इसकी कास्टिंग को भी दर्शकों और समीक्षकों से भरपूर सराहना मिल रही है। अलग-अलग पीढ़ियों और अभिनय शैलियों के कलाकारों का संतुलन इस फिल्म की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इस सफल कास्टिंग के पीछे जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का अहम योगदान माना जा रहा है।

मुकेश छाबड़ा का बड़ा सपना

फिल्म की सफलता के बीच मुकेश छाबड़ा ने अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य साझा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका उद्देश्य भारत के लिए 'बेस्ट कास्टिंग' कैटेगरी में ऑस्कर जीतना है। छाबड़ा का मानना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग विभाग को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि किसी भी फिल्म की नींव मजबूत करने में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है।

कास्टिंग विभाग को पहचान दिलाने की कोशिश

छाबड़ा ने कहा कि भारत में लगभग हर अवॉर्ड फंक्शन में कास्टिंग को वह सम्मान नहीं मिलता, जिसकी वह हकदार है। उनके मुताबिक, समय के साथ लोग यह समझेंगे कि सही कलाकारों का चयन ही फिल्म को यादगार बनाता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इतने बड़े लक्ष्य के बारे में खुलकर बोलते हुए उन्हें थोड़ी झिझक होती है, लेकिन उनका भरोसा है कि इसे सामने रखने से रास्ता जरूर बनेगा।

ऑस्कर में जुड़ रही नई कैटेगरी

गौरतलब है कि ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 से 'बेस्ट कास्टिंग' नाम की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस कैटेगरी में कास्टिंग डायरेक्टर्स ब्रांच के सदस्य वोट करेंगे और इसके बाद शॉर्टलिस्ट तैयार होगी। इस ऐलान के बाद से ही दुनिया भर के कास्टिंग डायरेक्टर्स में उत्साह देखा जा रहा है और मुकेश छाबड़ा इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं।

शानदार करियर और आने वाले प्रोजेक्ट

मुकेश छाबड़ा इससे पहले 'बजरंगी भाईजान', 'रॉकस्टार', 'जवान' और 'डंकी' जैसी बड़ी और सफल फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं। 'धुरंधर' के अलावा उन्होंने नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' की कास्टिंग भी पूरी कर ली है, जो अगले साल रिलीज होगी।

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस उपलब्धि

'धुरंधर' एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, सारा अर्जुन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आते हैं। फिल्म इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और इसने 'सैयारा' और 'कुली' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

प्रेमी व उसकी चार बहनो को गिरफ्तार कर मसौली पुलिस ने भेजा जेल

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। दो दिन पूर्व गोरखपुर से प्रेमी के घर शहाबपुर आयी प्रेमिका की हत्या मे शामिल प्रेमी व उसकी चार बहनो को गिरफ्तार कर मसौली पुलिस ने जेल भेज दिया है जबकि की हत्या मे शामिल प्रेमी के माता पिता अभी भी फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्यवाही जारी है।

बताते चले कि 16 दिसंबर की भोर मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम शहाबपुर मे हाइवे के किनारे स्थित कमलेश यादव के घर पर उस समय हड़कंप मच गया जब गोरखपुर की एक 30 वर्षीय युवती का रक्तरंजित शव कमलेश यादव के घर से बरामद हुआ मृतका कमलेश यादव के पुत्र संदीप यादव की प्रेमिका है जो आधी रात्रि अपने प्रेमी संदीप के घर मिलने आयी थी। हत्या की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के आला अधिकारियो ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस अधीक्षक ने घटना के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिये थे।

. (24 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम)

मंगलवार की भोर शहाबपुर मे हुई गोरखपुर की ममता यादव की हत्या के बाद मसौली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लेकिन परिजनों के न आने पर मंगलवार को शव का पंचनामा नहीं हो सका बुधवार को पोस्टमार्टम हॉउस पहुंचे मृतका के भाई अभिषेक यादव एव पिता राजकिशोर की मौजूदगी मे शव का पोस्टमार्टम किया गया तथा अभिषेक यादव की तहरीर पर प्रेमी संदीप यादव, पिता कमलेश यादव, माता संतोष कुमारी व बहने सुधा, निधि, मीरा, कंचन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर संदीप को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया तथा बहनो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि प्रेमी संदीप यादव के माता पिता अभी तक फरार है।

यूपी में पेट्रोल पंप खोलना अब चुटकियों का काम, योगी सरकार ने आसान की प्रोसेस, जानिए नए नियम

योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है

(जीएनएस)।

लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों और बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों पर चर्चा भरपूर है, मगर अभी तक इतना अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ है कि पेट्रोल-डीजल के बिना गुजारा हो सके पेट्रोल-डीजल की खपत बरकरार है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने

कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने आदेश जारी कर दिया नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए केवल राजस्व, बिजली, लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही एनओसी लेना आवश्यक होगा। अन्य विभागों के लिए आवेदक द्वारा दिया गया स्वघोषणा पत्र ही मान्य माना जाएगा।

बिहार और मध्यप्रदेश के बीच खेल अवसंरचना, सुविधाओं और ज्ञान साझा करने पर बनी सहमति

(जीएनएस)।

बिहार और मध्य प्रदेश खेल विकास पर सहयोग करने के लिए एक औपचारिक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और ज्ञान साझाकरण को शामिल किया गया है। योजना में बिहार के एथलीटों के लिए आरक्षित प्रशिक्षण सीटें, संयुक्त कोचिंग पहल और एमपी सुविधाओं के भीतर एक बिहार-प्रेरित कोचिंग ढांचे की स्थापना शामिल है।

बिहार और मध्यप्रदेश के बीच खेल अवसंरचना, खेल सुविधाओं और ज्ञान साझा करने को लेकर आपसी सहमति बनी है। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी से मुलाकात के बाद खेल के क्षेत्र में सहयोग को

लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनाई।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में बिहार की खेल मंत्री का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों के बीच खेल विकास के लिए समन्वय, तालमेल और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण और निदेशक हिमांशु सिंह भी विशेषज्ञों के साथ मौजूद रहे।

बैठक के दौरान दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। मध्यप्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी ने बिहार को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की विभिन्न खेल अकादमियों में बिहार के खिलाड़ियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। शूटिंग, तीरंदाजी, बॉक्सिंग और वाटर स्पोर्ट्स सहित कई खेलों में बिहार के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी।

इस बात पर भी सहमति बनी कि जिन खेलों के लिए बिहार में अभी आधारभूत संरचना पूरी तरह विकसित नहीं है, उन खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोनों राज्यों के बीच खेल ज्ञान, प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के साथ निरंतर सहयोग और समन्वय पर सहमति जताई गई।

मुंबई में भीख मांग रही ये महिला क्या सच में हैं फेमस किक्रेटर की पत्नी? आखिर क्या है सच्चाई

(जीएनएस)।

मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाली एक महिला के वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इसकी वजह, वीडियो में नजर आ रही महिला का दावा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भीख मांग कर गुजारा करने वाली इस महिला ने खुद को मशहूर किक्रेटर सलीम दुरानी की पत्नी बता कर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या ये सच में मशहूर क्रिकेटर सलीम दुरानी की पत्नी हैं और अगर हां तो कैसे इस बत्तर हालत में पहुंच गई?

याद रहे दो साल पहले मशहूर किक्रेटर सलीम दुरानी जिनको ये महिला अपना पति बता रही है उनका निधन दो साल पहले हो गया है। रेखा श्रीवास्तव नाम की इस उम्रदराज महिला ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि अपने क्रिकेटर पति सलीम दुरानी के साथ वो आलीशान जिंदगी जीती थी।

इंस्टाग्राम पर ये वीडियो तरुन मिश्रा नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में शख्स ने बताया कि इस महिला को मुंबई के बेलापुर मेट्रो स्टेशन के बाहर बेहद लाचार हालत में भीख मांगते देखा गया है। जिसके बाद इसे एक आश्रम में लाया गया और इनका हुलिया दुरुस्त किया गया।

दुबई में एयरलाइंस चलाती थी, राजा-महाराजाओं से होती थी मुलाकात

इस वीडियो में नजर आ रही रेखा श्रीवास्तव नाम की महिला ने बताया कि वो दुबई में एयरलाइंस कंपनी चलाती थी। अपने क्रिकेटर पति सलीम दुरानी के साथ देश-विदेश में होने वाले मैचों में जाती थी। इस दौरान वो उसकी मुलाकात राजा-महाराजाओं समेत देश-विदेश की जानी-मानी हस्तियों से होती रहती थी। वीडियो में एक जगह ये महिला अंग्रेजी में सिग्नेचर करती भी नजर आ रही है।

वीडियो में जब उससे पूछा गया कि इतने बड़े किक्रेटर की पत्नी कैसे इस हालत में पहुंची? कैसे वो इस तरह आर्थिक तौर पर मजबूर हो गई कि उन्हें मुंबई की सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरना पड़ रहा था। इस पर महिला ने बताया कि उनके पास अपना बंगला था, लेकिन उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा।

हालांकि इस वीडियो में नजर आ रही महिला रेखा श्रीवास्तव द्वारा किए गए दावे की पुष्टि नहीं है। वीडियो में सामने आने के बाद अभी तक क्रिकेटर सलीम दुरानी के परिवार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

साल 2026 में युवाओं की लगी लॉटरी! जानें किस-किस विभाग में योगी सरकार भरेगी 1.5 लाख खाली पद?

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नया साल उम्मीदों की सौगात लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्चस्तरीय बैठक के बाद 2026 में विभिन्न विभागों में करीब 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की हरी झंडी दे दी है।

यह महा-भर्ती अभियान न केवल युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि योगी सरकार को 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाएगा। आइए, इस पूरे प्लान को विस्तार से समझते हैं..कहां कितनी वैकेंसी, अब तक कितनी नौकरियां दी गईं और इसका युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? 2026 में कहां-कितनी भर्तियां?

योगी सरकार ने विभागवार खाली पदों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। सबसे ज्यादा वैकेंसी पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगीः- पुलिस विभाग 50,000

30,000 आरक्षी, 5,000 सब-इंस्पेक्टर, अन्य 15,000

शिक्षा विभाग

50,000 सहायक अध्यापक, लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि

राजस्व विभाग 20,000

मुख्य रूप से लेखपाल

अन्य विभाग (स्वास्थ्य, कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार आदि) 30,000 विभिन्न पद

कुल 1.5 लाख+

भर्ती के विज्ञापन अंतिम चरण में हैं, कुछ विभागों में प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सभी भर्तियां पारदर्शी और मेरिट आधार पर होंगी, जैसा सरकार का दावा है।

योगी सरकार (2017 से अब तक) का 'मिशन रोजगार' काफी चर्चित रहा। आधिकारिक दावों और रिपोर्ट्स के अनुसारः-

2017 से 2025 तक (साढ़े 8 साल में): 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं।

इनमें पुलिस में सबसे ज्यादा - करीब 2.19 लाख पदों पर भर्ती।

सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से, बिना किसी सिफारिश या घोटाले के।

2026 की 1.5 लाख भर्तियां पूरी होने पर कुल 10 लाख का रिकॉर्ड बनेगा - यूपी की किसी सरकार का पहला ऐसा कीर्तिमान।

क्यों खास है यह अभियान?

पारदर्शिता पर जोरः पिछली सरकारों में भर्तियों में धांधली के आरोप लगते थे, लेकिन योगी सरकार ने डिजिटल और मेरिट आधारित प्रक्रिया अपनाई।

युवाओं का भरोसाः लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, खासकर पुलिस और शिक्षक भर्ती के लिए।

अर्थव्यवस्था को बूस्टः सरकारी नौकरियां न केवल रोजगार देंगी, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगी।

अन्य प्रयासः सरकार टरटए, स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी लाखों जॉब्स क्रिएट कर रही है।

पीलीभीतः ठंड व शीतलहर से बचाव हेतु नगर पालिका ने 30+ स्थानों पर अलाव लगाए—राहगीर समस्याओं के लिए हेल्पलाइन जारी

(जीएनएस)।

पीलीभीत। नगर पालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में ठंड व शीतलहर के प्रकोप से राहगीरों व जनमानस की सुरक्षा के लिए कई प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये अलाव पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट (सीआरओ कार्यालय), जिलाधिकारी आवास, अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन, निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, तिकोनिया पार्क, ऑफिसर कॉलोनी, विकास भवन, नकटादाना चौराहा, साईधाम मंदिर, केजीएन रेन बसेरा, मंत्री कार्यालय संजय रॉयल पार्क, जिला अस्पताल, गौहनिया चौराहा, नगर पालिका कार्यालय, रेलवे स्टेशन चौराहा, छतरी चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, नौगवां चौराहा, रोडवेज रेन बसेरा, लेखराज चौराहा, बरेली दरवाजा, हिजड़ो वाली मस्जिद, शरीफ खान चौराहा, गैस चौराहा, चावला चौराहा, थाना सुनगढ़ी, आवास विकास चौराहा, जलकल प्रांगण, खकरा व रंगीलाल चौराहा सहित सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं।

अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ये अलाव ठंड से प्रभावित लोगों को गर्माहट प्रदान करेंगे। यदि किसी को समस्या हो, तो सफाई व खाद्य निरीक्षक को मोबाइल नंबर 9369649100 पर संपर्क कर सूचित किया जा सकता है।

नगर पालिका की इस पहल से सर्दी के मौसम में राहगीरों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने अपील की है कि लोग सतर्क रहें व अलाव का

नगर निगम की जमीन पर प्रशासन की मुहर, बोर्ड लगाकर कब्जेदारों को चेतावन

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ की तहसील सरोजनी नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिजनौर में नगर निगम व तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम की बहुमूल्य भूमि को अवैध कब्जों से सुरक्षित कराया। नगर निगम लेखपाल अनुपम कुमार एवं तहसील लेखपाल आदेश शुक्ला द्वारा ग्राम बिजनौर में स्थित नगर निगम की भूमि गाटा संख्या 527, 2450, 2450/स, 1919, 1919 (2), 448 एवं 956 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों व स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को चिन्हित किया तथा नगर निगम की भूमि को सुरक्षित करते हुए नगर निगम का चेतावनी बोर्ड स्थापित

किया। साथ ही अवैध कब्जेदारों को सख्त हिदायत दी गई कि यदि दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध कब्जा करने वालों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, निर्माण परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

मण्डलायुक्त ने बी, सी, डी श्रेणी वाले विभागों को कार्यों में तेजी लाते हुए 'ए' श्रेणी में लाने के दिए निर्देश

मण्डलायुक्त ने जिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष्मान योजना के तहत इंम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उल्लिखित करते हुए बैनर लगाये जाने के निर्देश दिए

कार्यदायी संस्थाओं को निमार्णाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित सयमसीमा में पूर्ण कराये जाने के दिए निर्देश

प्रयागराज 18 दिसंबर।

मण्डलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरूवार को गांधी सभागार में ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, निर्माण परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्माण परियोजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति लाये जाने एवं कार्यदायी संस्थाओं को निमार्णाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित सयमसीमा में पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बी, सी, डी श्रेणी वाले विभागों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए है।

मण्डलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किए जाने एवं बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराये जाने के लिए कहा है। कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न होने पाये। मण्डलायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचओ के द्वारा शुगर एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों की जांच करने के बाद जो लोग रेफर किए जाये, सम्बंधित एमओआईसी ऐसे लोगो की जांच करते हुए उनका उचित उपचार करें। मण्डलायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लोगो का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए कहा। उन्होंने जिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष्मान योजना के तहत इंम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उल्लिखित करते हुए बैनर लगाये जाने का निर्देश दिया है, जिससे कि लोगो को ऐसे अस्पतालों के बारे में और उपचार के बारे में जानकारी हो सके।

मण्डलायुक्त ने सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए नहरों में सिल्ट सफाई के कार्य को अनिवार्य रूप से 21 दिसम्बर तक पूर्ण कराये जाने एवं फीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने स्ट्रीट वेण्डरों के लोन से सम्बंधित आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिया है। छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति से सम्बंधित कार्यवाही को समय से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने अध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है। सामूहिक विवाह योजना में प्रयागराज में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति ठीक न पाये जाने पर उन्होंने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सत्यापन का कार्य शादी से पहले अवश्य करा लिया जाये। पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, फैमिली आईडी, जल जीवन मिशन सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

मण्डलायुक्त ने नई सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। कौशाम्बी जनपद के डी श्रेणी में होने पर मण्डलायुक्त ने पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए रैकिंग में सुधार लाये जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह से सड़क अनुरक्षण कार्य में जनपद फतेहपुर के सी श्रेणी में होने पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को कार्य में प्रगति लाते हुए श्रेणी में सुधार लाने के निर्देश दिए है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रयागराज श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी फतेहपुर श्री रविन्द्र सिंह, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी, जिलाधिकारी कौशाम्बी श्री अमित पाल शर्मा सहित सभी सम्बंधित विभागों के मण्डलीय अधिकारी ऑनलाइन व संयुक्त विकास आयुक्त श्री मत्स्य नाथ बैठक में उपस्थित रहे।

लखनऊ सुरक्षा व्यवस्था परखने सड़कों पर उतरे अधिकारी, चौक से टुड़ियागंज तक पैदल मार्च

(जीएनएस)।

लखनऊ। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डीसीपी पश्चिम, एसीपी चौक और चौक कोतवाली प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया रूट यह फ्लैग मार्च चौक क्षेत्र से शुरू होकर टुड़ियागंज तक निकाला गया। उद्देश्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा का अहसास कराना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना। प्रमुख गतिविधि अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों और जनता से संवाद किया तथा अतिक्रमण व सुरक्षा

मानकों के संबंध में निर्देश दिए। इस मार्च के दौरान पुलिस ने दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।

किक से विरोधियों को चैन की नींद सुलाने वाले फाइटर तवनचाई, पहली कमाई का खुलासा किया

(जीएनएस)।

पहली कमाई चाहे कितनी भी हो, सभी को हमेशा याद रहती है। थाई सुपरस्टार तवनचाई को भी मैच से हासिल हुई धनराशि की यादें आज भी उनके मन में तरोताजा हैं। सात साल की उम्र में मॉय थाई की शुरूआत करने वाले बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह आगे जाकर स्ट्राइकिंग की दुनिया का एक बड़ा सितारा बन जाएगा।

अब यही सुपरस्टार 19 दिसंबर को होने वाले डठए उँस्त्रङ्गल्लश्रँस्त्र के आखिरी इवेंट ONE Friday Fights 137 के अंतिम मैच में चीन की लिउ मेंगयैंग का सामना करेंगे। मौजूदा समय में डठए फेदरवेट मॉय थाई वर्ल्ड चैंपियन का लक्ष्य इस किकबॉक्सिंग मैच को जीतकर दूसरा खिताब हासिल करने की ओर अग्रसर होने का होगा।

एक साल की ट्रेनिंग के बाद मिला फल

थाईलैंड के हजारों युवाओं की तरह ही तवनचाई ने बेहद कम उम्र से अपने राष्ट्रीय खेल मॉय थाई में दो-दो हाथ शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक ऐसी ही फाइट को याद किया, जब उन्हें 800 बाहत (थाई मुद्रा) हासिल हुई।

26 वर्षीय चैंपियन ने उस पल को याद करते हुए कहा, "एक साल के आसपास ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पटाया के एक बार में फाइट करने का मौका मिला और मैंने अपने विरोधी को पहले राउंड में लेफ्ट किक से ढेर कर दिया। मुझे विदेशी सैलानियों से 24 अमेरिकी डॉलर हासिल हुए। मुझे बहुत खुशी हुई थी।"

आगे चलकर कमाया और भी बड़ा नाम

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को मॉय थाई मार्शल आर्ट्स का गढ़ कहा जाता है और यहीं आकर उन्होंने अपनी कामायबी की नई इबारत लिखी। उन्होंने 14 वर्षीय की आयु में प्रतिष्ठित लुम्पिनी स्टेडियम में डेब्यू किया और ढेर सारे खिताब अपने नाम किए।

शानदार प्रदर्शन की वजह से वह 2021 में डठए उँस्त्रङ्गल्लश्रँस्त्र में आए और आते ही दर्शकों पर छा गए। तवनचाई ने अब तक 12 मुकाबलों में से 10 में शानदार जीत हासिल की हैं। अब उनका लक्ष्य दो बेल्टों को एक साथ अपने कंधों पर रखना है।